SHRI MORARJI DESAI: It is difficult to give an estimate. What has been done is that we have instructed them that when I go out no police officer should be called from other district for that purpose and only local policemen should do whatever they have to do and that arrangements should be kept to the minimum. If meetings are for party purposes, the party will bear the expenses; government will not bear any of that expenditure. That is what has been said.

श्री रूप नाथ सिंह यादव : क्या यह सही है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू या श्रीमती इंदिरा गांधी पर पचास हजार रुपया प्रतिदिन खर्च होता था ?

SHRI MORARJI DESAI: I do not know; there may be large expenditure even on me; I do not know, I will have to find out.

Licences for Machine made Carpets

*605. SHRI FAQUIR ALI ANSARI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to lay a statement showing:

(a) the total number of licences given for the manufacture of machine made carpets in the country during the last 5 years;

(b) the names of the firms to whom these licences were given and when these licences were given;

(c) the basis of giving these licences to them;

(d) whether Government are aware that most of these firms or persons have not so far set up industries to manufacture carpets;

(e) if so, the particulars thereof;

(f) whether Government propose to withdraw the licences from these defaulters; and

(g) if so, when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (g). The only industrial licence issued during the last five years (April 1973 to March 1978) pertains to M/s. Modi Carpets Ltd. Modinagar to which a licence was issued in May 1976 for the manufacture of tufted carpets. This licence was given during the former Government's time in accordance with the then existing policy on the subject. From the records, it is seen that the licence was then given on the basis, inter alia, that the unit was export-oriented, the supply and demand relating to the raw material afforded scope for the unit and the unit was being set up in a backward area.

This unit is in advanced stage of implementation and is expected to go into commercial production in the near future. It is, therefore, not considered appropriate to withdraw the licence in this case.

श्री फकीर अली अंसारी : मंत्री महोदय ने बताया है कि—मोदी कारपेट को जो लाइसेंस दिया गया है वह उस वक्त की कच्चे माल की उपलब्धता को देखते हुए और इसकी निर्यात उन्मुखता को देखते हुए दिया गया था। क्या सरकार अभी भी इस बात से आश्वस्त या सैटिसफाइड है कि वही स्थिति आज भी मौजूद है ? क्या मंत्री महोदय सदन को आश्वासन देंगे कि भविष्य में इस प्रकार के उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे बेरोजगारी का मसला उत्पन्न हो ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : न सिर्फ भविष्य में बल्कि जब से नई सरकार अस्तित्व में आई है और नई नीति बनी है किसी इस प्रकार के नए उद्योग को नहीं दिया है और भविष्य में देने का सवाल ही नहीं है। यह चीज पहले से ही तय हो चुकी थी और अगले एक दो महीने में यह कारखाना प्रोडक्शन में चला जाएगा और अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री फकीर अली अंसारी : मोदी कारपेट लिमिटेड किस प्रकार के कच्चे माल का इस्तेमाल करेगा ? क्या इस में ऊन इस्तेमाल होगी जिसकी देश में कमी है और खादी

ग्रामोद्योग और हाथ के बने ऊनी कालीन उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है और उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है ?

यह कारखाना किस स्थान पर लग रहा है? क्या सरकार ने उस स्थान को बैकवर्ड एरिया घोषित किया है ? यदि नहीं तो इस बारे में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है क्योंकि इनको लाइसेंस पिछड़े जिले में लगाने के लिए दिया गया था ? इसमें क्षेत्रीय जनता को कितना रोजगार मिलेगा ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितने लोगों को काम मिलेगा इसके लिए मुझे नोटिस की जरूरत है। जहां तक रा-मेटीरियल का सवाल है इस समय कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। जैसे मैंने कहा है कोई नई मशीन से कारपेट बनाने वाले कारखाने का इजाजत देने का सवाल ही नहीं उठता है।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Maharashtra-Karnataka Boundary Dispute

*596. SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 54 on the 6th April, 1977 regarding Maharashtra-Karnataka, Boundary dispute and state the precise details of the endeavour made by Government during the period of one year, to settle the Maharashtra-Karnataka Boundary dispute as early as possible?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): The Government have every desire that this issue should be resolved as early as possible and in a spirit of mutual cooperation and goodwill. Now that new Governments have assumed office in Karnataka and Maharashtra, we intend to discuss the question with them with a view to find mutually acceptable solutions.

चम्बल नदी पर राजघाट पुल का निर्माण कार्य

*597. **श्री छबिराम अर्गल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री आगरा-बम्बई राजपथ के बीच मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा पर राजघाट पुल के काऊंटिंग ब्रिज के बारे में 20 जुलाई, 1977 के अल्प सूचना प्रश्न 22 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश-राजस्थान सीमा पर आगरा-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ पर चम्बल नदी पर राजघाट पुल का निर्माण कार्य दिसम्बर, 1978 तक पूरा हो जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो कितना कार्य पूरा हो चुका है और कितना कार्य अभी बाकी है;

(ग) क्या 297 लाख रुपये की लागत वाले इस पुल को वर्ष 1978 के अन्त तक पूरा करने के लिए इसके कार्य की गति तेज करने हेतु प्रयास किये जाएंगे ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त पुल के निर्माण कार्य में इस समय कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (घ). ठेका करार के अनुसार, कार्य दिसम्बर, 1978 तक पूरा किया जाना है। भूमितल की जांच का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। 7 नयी नीवों में से 3 नीवों पर कार्य पूरा हो चुका है। जबकि चौथी का कार्य पूरा होने को है। शेष 3 नीवों का कार्य प्रगति के अग्रिम चरणों में है। 3 पायों का निर्माण कार्य किया जा रहा है और नीव के नीचे पिलाई (ग्राउटिंग) कार्य प्रगति में है। अवभूत प्रकार की चट्टान के कारण राक-डीपर से अपेक्षित नीवों के धसाने के कारण तथा पानी के भारी प्रवाह के कारण, कई कुआं-नीवों पर न्यूमैटिक संयंत्रों के प्रयोग और कुछ सीमेंट की कमी